Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

ECONOMIC REFORMS SINCE 1991

After forty years of planned development, India has been able to achieve a strong industrial base and became self-sufficient in the production of food grains. Nevertheless, a major segment of the population continues to depend on agriculture for its livelihood. In 1991, a crisis in the balance of payments led to the introduction of economic reforms in the country. This unit is an appraisal of the reform process and its implications for India.

आर्थिक सुधार 1991 से

नियोजित विकास के चालीस वर्षों के बाद, भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार तथा खाद्यन्नों के उत्पादन में स्व–निर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसके बावजूद, जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 1991 में, भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

After studying this chapter, the learners will

- **understand the background of the reform policies introduced in India in 1991**
- **understand the mechanism through which reform policies were introduced**
- **comprehend the process of globalisation and its implications for India**
- **be aware of the impact of the reform process in various sectors.**

इस अध्याय को पढ़न के बाद आप

- 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे;
- सुधार नीतियों को आरंभ किये जाने की प्रक्रिया को समझंगे;
- वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे;
- विभिन्न क्षेत्रकों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को जानेंगे।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

INTRODUCTION

You have studied in the previous chapter that, since independence, India followed the mixed economy framework by combining the advantages of the capitalist economic system with those of the socialist economic system. Some scholars argue that, over the years, this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws, which were aimed at controlling and regulating the economy, ended up instead in hampering the process of growth and development.

परिचय

आपने पिछले अध्याय में पढ कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँच को अपनाया। इसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एक साथ थीं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम–कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक संवृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

In 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt — the government was not able to make repayments on its borrowings from abroad; foreign exchange reserves , which we generally maintain to import petroleum and other important items, dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight. The crisis was further compounded by rising prices of essential goods.

वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिज़र्व पंद्रह दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

we will look at the background of the crisis, measures that the government has adopted and their impact on various sectors of the economy.

इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों पर उन नीतियों के प्रभावों पर विचार करेंगे।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

BACKGROUND

The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in the 1980s.

पृष्ठभूमि

इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

When expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from banks and also from people within the country and from international financial institutions. When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our exports.

the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion.

जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं।

गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई।

the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion.

गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुइ

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The income from public sector undertakings was also not very high to meet the growing expenditure. At times, our foreign exchange, borrowed from other countries and international financial institutions, was spent on meeting consumption needs.

बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिये सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. Prices of many essential goods rose sharply. Imports grew at a very high rate without matching growth of exports.

1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़न लगीं। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की संवृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था।

There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needed to be paid to international lenders. Also no country or international funder was willing to lend to India.

अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं कोई देश या अतंर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

India approached the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), popularly known as World Bank and the International Monetary Fund (IMF), and received $7 billion as loan to manage the crisis.

For availing the loan, these international agencies expected India to liberalise and open up the economy by removing restrictions on the private sector, reduce the role of the government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries

उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक (आई.बी.आर. डी.) जिसे सामान्यत: 'विश्व बैंक' के नाम से भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को 7 बिलियन डॉलर का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। किंतु, उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाइं; जैसे, सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जायेंगे।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

India agreed to the conditionalities of World Bank and IMF and announced the New Economic Policy (NEP). The NEP consisted of wide ranging economic reforms. The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. This set of policies can broadly be classified into two groups: the stabilisation measures and the structural reform measures.

भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शतें मान लीं और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी संवृद्धि में आनेवाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

balance of payments and to bring inflation under control. In simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves and keep the rising prices under control. On the other hand, structural reform policies are long-term measures, aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy.

जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में, इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The government initiated a variety of policies which fall under three heads viz., liberalisation, privatisation and globalisation.

इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ कीं। इनके तीन उपवर्ग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

LIBERALISATION

Liberalisation was introduced to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy. Though a few liberalisation measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment, reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. Let us study some important areas, such as the industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign exchange markets and trade and investment sectors which received greater attention in and after 1991.

उदारीकरण

उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को 'मुक्त' करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात–निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे। किंतु, 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए, हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र हैं–औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर–सुधार, विदेशी विनिमय बाज़ार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, जिनपर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया था।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Deregulation of Industrial Sector: In India, regulatory mechanisms were enforced in various ways (i) industrial licensingunder which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced (ii) private sector was not allowed in many industries (iii) some goods could be produced only in small-scale industries, and (iv) controls on price fixation and distribution of selected industrial products.

औद्योगिक क्षेत्रक का विनियमीकरण : भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था (क) सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी; (ख) अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था; (ग) कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories — alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs and pharmaceuticals.

1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रोनिकी, विमानन तथा औषधि–भेषज;

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Financial Sector Reforms:

Financial sector includes financial institutions, such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. The financial sector in India is regulated by the Reserve Bank of India (RBI).

वित्तीय क्षेत्रक सुधार : वित्त के क्षेत्रक में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार जैसी वित्तीय संस्थाएँ सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्रक का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

One of the major aims of financial sector reforms is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector. This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI.

वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्रक के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्रक के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The reform policies led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign. Foreign investment limit in banks was raised to around 74 per cent. Those banks which fulfil certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI and rationalise their existing branch networks. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interests of the account-holders and the nation. Foreign Institutional Investors (FII), such as merchant bankers, mutual funds and pension funds, are now allowed to invest in Indian financial markets.

सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्रक में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूँजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74 प्रतिशत कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करनेवाले बैंक अब रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएँ खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक यक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश–विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है– पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही हैं। विदेशी निवेश संस्थाओं(एफ.आई.आई) तथा व्यापारी बैंक, म्युचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाज़ारों में निवेश की अनुमति मिल गई है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Tax Reforms: Tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public expenditure policies, which are collectively known as its fiscal policy. There are two types of taxes: direct and indirect. Direct taxes consist of taxes on incomes of individuals, as well as, profits of business enterprises. Since 1991, there has been a continuous reduction in the taxes on individual incomes as it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion.

कर व्यवस्था में सुधार : इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर–वंचन होता है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The rate of corporation tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. Efforts have also been made to reform the indirect taxes, taxes levied on commodities, in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodities.

निगम कर की दर, जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे–धीरे कम कर दी गई है। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं जैसे, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये गये कर–ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाज़ार की रचना की जा सके।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Foreign Exchange Reforms:
The first important reform in the external sector was made in the foreign exchange market. In 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payments crisis, the rupee was devalued against foreign currencies.

विदेशी विनिमय सुधार: विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाज़ार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Trade and Investment Policy Reforms:

Liberalisation of trade and investment regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investments and technology into the economy. The aim was also to promote the efficiency of local industries and adoption of modern technologies.

व्यापार और निवेश नीति सुधार:

अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The trade policy reforms aimed at (i) dismantling of quantitative restrictions on imports and exports (ii) reduction of tariff rates and (iii) removal of licensing procedures for imports. Import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. Quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agricultural products were also fully removed from April 2001.

व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे : (क) आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, (ख) प्रशुल्क दरों में कटौती और (ग) आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड, अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल, 2001 से कृषि पदाथों और औद्योगिक उपभोक्ता पदाथों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

PRIVATISATION

It implies shedding of the ownership or management of a government owned enterprise. Government companies are converted into private companies in two ways

(i)by withdrawal of the government from ownership and management of public sector companies and or

(ii)(ii) by outright sale of public sector companies.

निजीकरण

इसका तात्पर्य है, किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्रक की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं:

(क) सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा

(ख) सार्वजनिक क्षेत्रक की कपंनियों को सीधे बेच दिया जाना।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Privatisation of the public sector enterprises by selling off part of the equity of PSEs to the public is known as disinvestment. The purpose of the sale, according to the government, was mainly to improve financial discipline and facilitate modernisation.

किसी सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार, इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Navratnas and Public Enterprise Policies

The Central Public Sector Enterprises are designated with different status. A few examples of public enterprises with their status are as follows: (i) Maharatnas – (a) Indian Oil Corporation Limited, and (b) Steel Authority of India Limited, (ii) Navratnas – (a) Hindustan Aeronautics Limited, (b) Mahanagar Telephone Nigam Limited; and (iii) Miniratnas – (a) Bharat Sanchar Nigam Limited; (b) Airport Authority of India and (c) Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited.

'नवरत्न' और सार्वजनिक उद्यम नीतियां

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किये गए हैं। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार हैं: (प) महारत्न– (अ) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और (ब) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (पप) नवरत्न (अ) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, (ब) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (पपप) लघुरत्न– (अ) भारत संचार निगम लिमिटेड, (ब) एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया और (स) इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

GLOBALISATION

Although globalisation is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy, it is a complex phenomenon. It is an outcome of the set of various policies that are aimed at transforming the world towards greater interdependence and integration. It involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. Globalisation attempts to establish links in such a way that the happenings in India can be influenced by events happening miles away. It is turning the world into one whole or creating a borderless world.

वैश्वीकरण

यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है, जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण एसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है, जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमामुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Outsourcing: This is one of the important outcomes of the globalisation process. In outsourcing, a company hires regular service from external sources, mostly from other countries, which was previously provided internally or from within the country (like legal advice, computer service, advertisement, security — each provided by respective departments of the company).

बाह्य प्रापण : वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट् परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत (संस्था) से नियमित सेवाएँ प्राप्त करती हैं। अधिकांशतः अन्य देशों से, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Many of the services such as voice-based business processes (popularly known as BPO or call centres), record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, book transcription, clinical advice or even teaching are being outsourced by companies in developed countries to India. With the help of modern telecommunication links including the Internet, the text, voice and visual data in respect of these services is digitised and transmitted in real time over continents and national boundaries.

अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहां तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी-छोटी संस्थाओं से ये सेवाएँ प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे, इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत शून्य से नौ तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Global Footprint!

Owing to globalisation, you might find many Indian companies have expanded their wings to many other countries. For example, ONGC Videsh, a subsidiary of the Indian public sector enterprise, Oil and Natural Gas Corporation engaged in oil and gas exploration and production has projects in 16 countries. Tata Steel, a private company established in 1907, is one of the top ten global steel companies in the world which have operations in 26 countries and sell its products in 50 countries. It employs nearly 50,000 persons in other countries. HCL Technologies, one of the top five IT companies in India has offices in 31 countries and employs about 15,000 persons abroad. Dr Reddy's Laboratories, initially was a small company supplying pharmaceutical goods to big Indian companies, today has manufacturing plants and research centres across the world.

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

विश्वस्तरीय पद–छाप

वैश्वीकरण के कारण, अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए, ओएनजीसी विदेश, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील, 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है, जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष दस वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। एचसीएल टैक्नोलॉजीज, भारत में शीर्ष पांच आईटी कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी–सी कंपनी थी, आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केन्द्र हैं

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

World Trade Organisation (WTO): The WTO was founded in 1995 as the successor organisation to the General Agreement on Trade and Tariff (GATT). GATT was established in 1948 with 23 countries as the global trade organisation to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes. WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade.

विश्व व्यापार संगठन: व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि (GATT) के परवर्ती विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय एसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएँ खड़ी नहीं कर पाए।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The WTO agreements cover trade in goods as well as services to facilitate international trade (bilateral and multilateral) through removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater market access to all member countries.

As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations and safeguards and advocating the interests of the developing world.

विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ान हेतु इसमें वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। एसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाज़ारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्वस्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है।

while developed countries file complaints over agricultural subsidies given in their countries, developing countries feel cheated as they are forced to open their markets for developed countries but are not allowed access to the markets of developed countries.

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

INDIAN ECONOMY DURING REFORMS: AN ASSESSMENT

In economics, the growth of an economy is measured by the Gross Domestic Product. Look at Table 3.1. The post– 1991 India witnessed a rapid growth in GDP on a continual basis for two decades. The growth of GDP increased from 5.6 per cent during 1980–91 to 8.2 per cent during 2007–12. During the reform period, the growth of agriculture has declined. While the industrial sector reported fluctuation, the growth of the service sector has gone up. This indicates that this growth is mainly driven by growth in the service sector.

सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था–एक समीक्षा

आइए, इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। सारणी 3.1 को देखें। 1991 के बाद से भारत में दो दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980–91 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2007–2012 में 8.2 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आयी। जहां औद्योगिक क्षेत्रक में उतार–चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्रक में वृद्धि बढ गई। इससे यह पता चलता है कि वृद्धि मुख्यत: सेवा–क्षेत्रक में वृद्धि के कारण हुई है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

During 2012-15, there has been a setback in the growth rates of different sectors witnessed post–1991. While agriculture recorded a high growth rate during 2013–14, this sector witnessed negative growth in the subsequent year. While the service sector continued to witness a high level of growth — higher than the overall GDP growth in 2014– 15, this sector witnessed the high growth rate of 9.8 per cent. The industrial sector witnessed a steep decline during 2012–13, in the subsequent years it began to show a continuous positive growth.

2012–15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रकों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आयी। जहां 2013–14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आयी, वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्रक की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। सेवा क्षेत्रक में ऊँची वृद्धि दर बनी रही, जो 2014–15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक थी। इस क्षेत्रक में अबतक का उच्च वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत रेकार्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्रक में 2012–13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात् बाद के वर्षों में बढ़ने लगा।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

The opening of the economy has led to a rapid increase in foreign direct investment and foreign exchange reserves. The foreign investment, which includes foreign direct investment (FDI) and foreign institutional investment (FII), has increased from about US $100 million in 1990-91 to US $ 30 billion in 2017-18. There has been an increase in the foreign exchange reserves from about US $ 6 billion in 1990-91 to about US $ 413 billion in 2018-19. India is one of the largest foreign exchange reserve holders in the world.

अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिज़र्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश (जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं) 1990–91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017–18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। भारत के विनिमय रिज़र्व का आकार भी 1990–91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018–19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिज़र्व का सातवां सबसे बड़ा धारक माना जाता है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

India is seen as a successful exporter of auto parts, engineering goods, IT software and textiles in the reform period. Rising prices have also been kept under control.

अब भारत वाहन, कल-पुर्जों, इंजीनियरी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाज़ार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया हैं।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Growth and Employment:

Though the GDP growth rate has increased in the reform period, scholars point out that the reform-led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country.

संवृद्धि और रोजगार :

यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित संवृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Reforms in Agriculture:

Reforms have not been able to benefit agriculture, where the growth rate has been decelerating. Public investment in agriculture sector especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages and research and extension (which played a crucial role in the Green Revolution), has fallen in the reform period. Further, the partial removal of fertiliser subsidy has led to increase in the cost of production, which has severely affected the small and marginal farmers. This sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in import duties on agricultural products, low minimum support price and lifting of quantitative restrictions on the imports of agricultural products. These have adversely affected Indian farmers as they now have to face increased international competition.

कृषि में सुधार : सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की संवृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्रक में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात् सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाज़ार संपर्कों और शोध–प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है (ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वूपूर्ण भूमिका रही थी)। साथ ही, उर्वरक सहायिकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदाथों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्रक की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Reforms in Industry: Industrial growth has also recorded a slowdown. This is because of decreasing demand of industrial products due to various reasons such as cheaper imports, inadequate investment in infrastructure etc. In a globalised world, developing countries are compelled to open up their economies to greater flow of goods and capital from developed countries and rendering their industries vulnerable to imported goods. Cheaper imports have, thus, replaced the demand for domestic goods. Domestic manufacturers are facing competition from imports. The infrastructure facilities, including power supply, have remained inadequate due to lack of investment. Globalisation is, thus, often seen as creating conditions for the free movement of goods and services from foreign countries that adversely affect the local industries and employment opportunities in developing countries.

उद्योगों में सुधार : औद्योगिक संवृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई माँग के कारण है। माँग में गिरावट के कई कारण हैं जैसे, सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूँजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं तथा उन्होंने अपने उद्योगों का आयतित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की माँग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण, बिजली सहित, आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण, प्रायः यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक-टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Disinvestment: Every year, the government fixes a target for disinvestment of PSEs. For instance, in 1991-92, it was targeted to mobilise Rs 2500 crore through disinvestment. The government was able to mobilise ` 3,040 crore more than the target. In 2017–18, the target was about ` 1,00,000 crore, whereas, the achievement was about ` 1,00,057 crore. Critics point out that the assets of PSEs have been undervalued and sold to the private sector. This means that there has been a substantial loss to the government. Moreover, the proceeds from disinvestment are used to offset the shortage of government revenues rather than using it for the development of PSEs and building social infrastructure in the country.

विनिवेश : प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991–92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड अधिक जुटा पाने में सफल रही। वर्ष 2017–18 में लक्ष्य तो लगभग 1,00,000 करोड के विनिवेश का था, पर उपलब्धि लगभग 1,00,057 करोड की रही। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने–पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड रहा है। साथ ही, विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही इसे सामाजिक आधारिक संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Reforms and Fiscal Policies:

Economic reforms have placed limits on the growth of public expenditure, especially in social sectors. The tax reductions in the reform period, aimed at yielding larger revenue and curb tax evasion, have not resulted in increase in tax revenue for the government. Also, the reform policies, involving tariff reduction, have curtailed the scope for raising revenue through custom duties. In order to attract foreign investment, tax incentives are provided to foreign investors which further reduced the scope for raising tax revenues.

सुधार और राजकोषीय नीतियां : आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रकों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ान ने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमाशुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं, इससे भी कर राजस्व क बढ़ा पाने की संभावनाएँ क्षीण हो गई हैं।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

CONCLUSION

The process of globalisation through liberalisation and privatisation policies has produced positive, as well as, negative results both for India and other countries. Some scholars argue that globalisation should be seen as an opportunity in terms of greater access to global markets, high technology and increased possibility of large industries of developing countries to become important players in the international arena.

निष्कर्ष

उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भाँति देखा जाना चाहिए क्योंकि विश्व बाज़ारों में बेहतर पहुँच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'महत्वपूर्ण' बनने का अवसर प्रदान कर रहा है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

On the contrary, the critics argue that globalisation is a strategy of the developed countries to expand their markets in other countries. According to them, it has compromised the welfare and identity of people belonging to poor countries. It has further been pointed out that market-driven globalisation has widened the economic disparities among nations and people.

दूसरी ओर, आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाज़ारों पर कब्जा करने की साजिश है। इनके अनुसार, वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन् उनकी पहचान भी खतरे में पड गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाज़ार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है।

it has increased the income and quality of consumption of only high-income groups and the growth has been concentrated only in some select areas in the services sector such as telecommunication, information technology, finance, entertainment, travel and hospitality services, real estate and trade, rather than vital sectors such as agriculture and industry which provide livelihoods to millions of people in the country.

इन्होंने केवल उच्च आयवर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है तथा सारी संवृद्धि कुछ इने–गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्र हैं – दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएँ, भवन निर्माण और व्यापार आदि। कृषि, विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्रक (जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं) इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Recap

➢**The economy was facing problems of declining foreign exchange, growing imports without matching rise in exports and high inflation. India changed its economic policies in 1991 due to a financial crisis and pressure from international organisations like the World Bank and IMF.**

पुनरावर्तन

भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ-साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड रहा था। फलस्वरूप, उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता माँगने पर उनके दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

In the domestic economy, major reforms were undertaken in the industrial and financial sectors. Major external sector reforms included foreign exchange deregulations and import liberalisation.

आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्रकों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय विनियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

With a view to improving the performance of the public sector, there was a consensus on reducing its role and opening it up to the private sector. This was done through disinvestment and liberalisation measures.

सार्वजनिक क्षेत्रक की कार्यकुशलता बढ़ान के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गईं।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

Globalisation is the outcome of the policies of liberalisation and privatisation. It means an integration of the economy of the country with the world economy

वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। इसका अर्थ आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

- **Outsourcing is an emerging business activity.**
- **The objective of the WTO is to establish a rule based trade regime to ensure optimum utilisation of world resources.**
- **During the reforms, growth of agriculture and industry has gone down but the service sector has registered growth.**

- बाह्य प्रापण: बाहरी देशों से व्यावसायिक सेवाओं की प्राप्ति एक उदीयमान व्यापारिक गतिविधि है।
- विश्व व्यापार संगठन का ध्येय एसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है, जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके।
- सुधारकाल में कृषि और उद्योगों की संवृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवाओं में उछाल आया है।

Liberalisation, Privatisation and Globalisation: An Appraisal
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण–एक समीक्षा

- **Reforms have not benefited the agriculture sector. There has also been a decline in public investment in this sector.**
- **Industrial sector growth has slowed down due to availability of cheaper imports and lower investment.**

- सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुँचा है। इस क्षेत्रक में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई है।
- औद्योगिक क्षेत्रक में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता ही आई है।